(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पर्यावरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव तथा उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मा निर्धारित किये गये है ।

(3) परिवेशी गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

(4) प्रमुख नगरों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारिण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं ।

(6) बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विर्जनोंको निर्धारित सीमाओं के रखने के लिए उद्योगों राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है ।

(7) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिये गये हैं तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाती है ।

(8) मल जल और अपवहन तन्त्र के निर्माण संवर्धन के लिए तथा मल जल शोधन के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं । इस प्रकार की स्कीमें केन्द्र सरकार की गंगा कार्य योजना के अंतगत कलकत्ता में शुरू की गई हैं ।

(9) साझे बहिःस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है ।

(10) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(11) मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत सभी वाहनों के लिए ठोस एवं द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं । भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन ठोस उत्सर्जन मानकों को 1 मार्च, 1990 लागू करने की सलाह दी है ।

(12) यानीय प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ।

(13) पैट्रोलियम उद्योग से पैट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके 1993 तक 0.15 ग्राम प्रतिलिटर तक लागाने का कहा गया है ।

(14) प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता को उसके द्वारा बनाए गए वाहन का प्रोटोटाइप सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा जांच करने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा उत्पाद के उत्सर्जन मानकों सहित नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप होने के बारे में एक प्रमाण पत्र देना अपेक्षित है । यह उपबन्ध अप्रल 1991 लागू हो गया है ।

(15) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी संस्थान (नीरी), नागपुर सड़कों पर चलने वाले वाहनों निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए एक देशी कैटलिटिक कनवर्टर बनाने के कार्य में लगा है ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

ECO-Destruction of the Himalayas

949. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that eco-destruction of the Himalayas portends a gra-

ve threat to the environmental stability of the entire Indian sub-continent;

(b) whether it is also a fact that forest cover in the Himalayas has been reduced considerably;

(c) whether a major part of penisular India depends crucially on the Himalayas for monsoon; and

(d) whether Government have formulated any plan to preserve the Himalayan eco-system and check deforestation of its slopes if so, what are the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) There is no conclusive evidence to show that the eco-destruction of the Himalayas poses a grave threat to the environmental stability of the entire Indian sub-cotinent.

(b) According to the 3rd and the latest assessment of the forest cover made by Forest Survey of India, Dehradun, based on the visual interpretation of satellite imageries pertaining to the period 1987—89, the actual, forest cover has not decreased in the Himalayas, except for Arunachal Pradesh in comparison to 2nd assessment of forest cover pertaining to the period 1985—87.

(c) No, Sir.

(d) The Govtrnment have taken following steps to preserve Himalayan ecosystem and check deforestation:

(i) G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development has been established to evolve effective strategies for management of natural resources and substantial development.

(ii) An integrated Action Oriented Programme in the Himalayan Region has been launched.

(iii) Guidelines have been issued to State Governments from time to time for protection of forest. Some of these guidelines are as follows:

(a) To avoid clear felling of natural forests and where such fellings are inevitable for restoration of crop or other silvicultural considerations, it should be restricted to areas not exceeding 10 hectares in the hills and 25 hectares in the plains.

(b) To consider banning of fellings in the hills above 1000 metres, at least for same years.

(c) To identify critical areas in the hills and mountains which require protection from felling of forests and need immediate vigorous afforestation.

(d) To set apart of the geographical areas as protected area like wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves etc.

(e) A massive afforestation programme including Social Forestry and Agroforestry under 20 Point Programme in all States and UTs. has been uaunched. Upto the end of VIIth five year plan, an area to the tune of 17.09 million hectares has been brought under afforestation.

(f) Government of India have issued kuidelines for peoples' participation in management and development of degraded forests and their active involvement in afforestation programme.

Notification issued under the Environment Protection Act

950. SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether by a notification issued on January 16, 1991 under the Environment Protection Act, the industries along the Ganga were required to fulfill certain pollution control standards by 31st December, 1991;

(b) whether the Supreme Court had also directed these units to file affidavits on the measures taken by them;

(c) whether Government have since relaxed this deadline and given one more year's time to these industries;